शब्द–ब्रह्म
E - ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका 17 जून 2016
पीअर रीव्यूड रेफ्रीड रिसर्च जर्नल

ग्रामीण जीवन का अर्थशास्त्र

डॉ. अरूणा कुसुमाकर
प्राध्यापक (अर्थशास्त्र)
शासकीय संस्कृत महाविद्यालय
इन्दौर, मध्यप्रदेश, भारत

शोध संक्षेप

भारत में कभी सात लाख गाँव थे । विभाजन के बाद इनकी संख्या छः लाख रह गयी । नगरीकरण की अवधारणा बलवती होने के बाद भी भारत की अधिसंख्य जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। भारत की ग्रामीण अर्थ व्यवस्था हजारों वर्षों में विकसित हुई है । हरेक गांव अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था के साथ परस्परावलंबी था । आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संबल प्रदान करने के लिए अनेक योजनायें चल रही हैं । प्रस्तुत शोध पत्र में इन योजनाओं के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर विचार किया गया है

प्रस्तावना

हमारे देश की अधिकतम जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। अतः भारत को गांवों का देश कहा जाता है। वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार 68.84 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। स्वतन्त्रता के समय देश के कर्णधारों ने एक ऐसे भारतीय समाज की परिकल्पना की थी , जिसमें समानता एवं सामाजिक न्याय पर आधारित विकास की समस्त संभावनाएँ मौजूद हो अर्थात गाँवों तथा शहरों के बीच सुविधाएँ एवं सम्पन्नता लगभग एक समान हो।

अध्ययन के उद्देश्य

ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना।

ग्रामीण विकास योजना की रणनीति का अध्ययन करना।

भारत के भावी विकास में ग्रामीण विकास का अध्ययन करना।

ग्रामीण विकास हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

अध्ययन विधि

प्रस्तुत शोध अध्ययन द्वितीयक संमको पर आधारित है। मौखिक चर्चा एवं विचार-विमर्श के आधार पर विश्लेषणात्मक पद्धति को अपनाया गया है।

विश्लेषण

यह सत्य है कि गाँवों में ही भारत की आत्मा बसती है। शहरीकरण की अंधी दौड़ के बावजूद असली भारत आज भी मुख्य रूप से गाँवों में ही बसता है, क्योंकि 68.84 प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका का प्रमुख साधन कृषि है। कृषि क्षेत्र 64 प्रतिशत श्रमशक्ति को जीविका उपलब्ध कराता है। देश के सफल राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि का योगदान लगभग 16 प्रतिशत है। वास्तव में ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भारत जब स्वतन्त्र हुआ तब दो अमूल्य संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे - प्रथम देश में सर्वत्र उपलब्ध उर्वरा भूमि , द्वितीय खेतिहर आबादी, किन्तु देश के कर्णधारों ने खेतिहर

आबादी को नकारा ही नहीं वरन् बोझ माना। देश जब आजाद हुआ तब हमारी जनसंख्या 40 करोड़ अर्थात 80 करोड़ हाथों को यदि 16 करोड़ हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि पर कृषि को प्राथमिकता दी जाती तो भारत आज विश्व का सबसे सम्पन्न देश होता।

यद्यपि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ग्रामीण विकास योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया किन्तु इन योजनाओं एवं कार्यक्रमों का पूर्ण लाभ ग्रामीणों को नही मिल पाया। यही कारण है कि इतने वर्षों में हमने विकास तो किया है किन्तु , फिर भी हम विकासशील राष्ट्रों की श्रेणी में ही अपना स्थान बना पाए हैं। वर्ष 2015-16 के बजट में ग्रामीण विकास की व्यूह रचना हेतु कुल व्यय का प्रावधान निम्नानुसार है-

ग्रामीण विकास पर व्यय

1 Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme 34699.00

2 Aajeevika - National Rural Livelihood Mission 2505.00

3 Rural Housing 10025.00

4 Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana 14291.00

5 Grants to National Institute of Rural Dev 50.00

6 Assistance to C.A.P.A.R.T.10.00

7 Management support to Rd~ Programmes and strengthening district planning process 130.00

8 BPl~ Survey 350.00

9 National Social Assistance Programme 9082.00

10 RURBAN Mission 300.00

11 Village Entrepreneurship 'Start-up'k~ Programme 200.00

Total Plan RD 71642.00

स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण विकास योजना की रणनीति के तहत अनेक योजनाएँ एवं कार्यक्रम क्रियान्वित किए गए जो इस प्रकार हैं- सामुदायिक विकास योजना (1952), राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम (1953) खादी एवं ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम (1957), ग्रामीण आवासीय परियोजना (1957), बहुउद्देशीय अनुसूचित जनजाति विकासखण्ड कार्यक्रम (1957), विशेष पैकेज कार्यक्रम (1960), गहन जिला कृषि क्षेत्र कार्यक्रम (1964), कुआं निर्माण कार्यक्रम (1966), ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम (1989), सूखा क्षेत्र पीड़ित कार्यक्रम (1970), ग्रामीण रोजगार नकदी योजना (1971)¬, लघु कृषक विकास एजेंसी (1971), जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम (1972), बीस सूत्रीय कार्यक्रम , 1977, ट्राइसम (1979) राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम (1981), नया बीस सूत्रीय कार्यक्रम (1982), ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (1989), इंदिरा आवास योजना (1993), सुनिश्चित रोजगार योजना (1993), गंगा कल्याण योजना (1997),स्वर्ण स्वरोजगार योजना (1999), प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (2000), प्रधानमंत्री सड़क योजना (2000), संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (2001), खेतीहर मजदूर बीमा योजना (2001), प्रधानमंत्री ग्रामीण जल संवर्द्धन योजना (2002) निर्मल ग्राम पुरस्कार (2005), राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (2005), राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (2005), भारत निर्माण योजना आदि।

ग्रामीण क्षेत्रों में सुनियोजित विकास की इन सभी योजनाओं का उद्देश्य कृषि का विकास करना , अनुसूचित जाति एवं जनजातियों की आर्थिक-सामाजिक स्थिति में सुधार लाना , ग्रामीण रोजगार में वृद्धि करना, गाँवों में आवास व्यवस्था सृदृढ़ करना , ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं को विकसित करना, गाँवों में बेकार पड़ी भूमि को कृषि योग्य बनाना तथा गाँवों की आधारिक संरचना का विकास कर देश के विकास को आगे

बढ़ाना है, किन्तु योजनाओं के उचित क्रियान्वय न होने के कारण आज भी गाँवों का उतना विकास नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए। अतः ग्रामीण विकास हेतु कुछ प्रमुख सुझाव इस प्रकार है-

भारत के विकास में आधारिक संरचना का विशेष महत्व है। अतः ग्रामीण विकास योजना रणनीति में सड़क, विद्युत, संचार, परिवहन, स्वास्थ्य एवं शुद्धजल आदि सुविधाओं को विकसित किया जाना आवश्यक है।

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उद्योगों में अधिक निवेश को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तथा कृषि आधारित उद्योगों को विकसित किया जाना चाहिए।

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि अनुसंधान का विस्तार किया जाना चाहिए।

ग्रामीण विकास योजना की रणनीति में गाँवों की भौगोलिक एवं संसाधन उपलब्धता के आधार पर लघु एवं कुटीर उद्योगों को विकसित किया जाना चाहिए।

ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक सजगता का प्रचार-प्रसार करके ग्रामीणों में जागृति लाना होगा।

ग्रामीण विकास योजनाओं एवं कार्यक्रमों की पर्याप्त जानकारी ग्रामीणों तक पहुँचाने की यवस्था की जानी चाहिए। गैर सरकारी संगठनों को ग्रामीण विकास रणनीति में सक्रिय भागीदार बनाना चाहिए।

शिक्षा देश के भावी विकास का प्रमुख आधार है। अतः गाँवों में प्राथमिक , माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के स्तरों पर अधिक जोर देना होगा।

ग्रामीण विकास से संबंधित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपने उत्तरदायित्वों को निष्ठापूवर्क एवं ईमानदारी से निभाने हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए तथा उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरस्कृत किया जाना चाहिए।

ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों हेतु सतत् निगरानी एवं मूल्यांकन किया जाना चाहिए। वास्तव में ग्रामीण विकास योजना की रणनीति को भावी भारत का आधार बनाने के लिए आवश्यक है कि ग्रामीण विकास योजना कार्यक्रमों को केवल कागजी कार्यवाही तक सीमित न रखकर यर्थार्थ में क्रियान्वित किया जाए तथा सही व्यक्ति को लाभान्वित किया जाए।

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध से स्पष्ट है कि ग्रामीण योजना की रणनीति वास्तव में भावी भारत के विकास का आधार है क्योंकि गाँव ही भारत की आत्मा है। अतः सबसे पहले आत्मा को विकसित करना होगा। ग्रामीण क्षेत्रो को शहरी क्षेत्रों के समकक्ष लाकर समता एवं सामाजिक न्याय पर आधारित समाज की स्थापना करके उच्चे आर्थिक संवृद्धि दर प्राप्त कर भारत को विश्व की एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रन्थ

1 आर्थिक समीक्षा- 2013-14- आर्थिक साख्यिकी संचालनालय, दिल्ली।

2 भारतीय अर्थव्यवस्था-2015 साहित्य भवन प्रकाशन, दिल्ली।

3 कुरूक्षेत्र - नवम्बर 2005, अगस्त 2006।

4 ग्रामीण विकास मंत्रालय की वेबसाइट।

5 समसामयिकी वार्षिकी 2015, साहित्य भवन प्रकाशन, आगरा।